

बंगाल में हिंसा जारी

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता कोलकाता। पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देर रात मध्यमग्राम में उन पर चार राउंड फायरिंग की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चंद्रनाथ के सीने में तीन गोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार चला रहे उनके ड्राइवर को भी गोली लगी है, जिनका एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंद्रनाथ, सुवेंदु के काफी करीबी थे। पिछले पांच साल से उनके साथ साथे की तरह रह रहे थे। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ को मध्यमग्राम में उस वक्त निशाना बनाया गया, जब वो किसी काम के सिलसिले में अपनी कार से जा रहे थे। कार उनका ड्राइवर चल रहा था। चश्मदीनों का कहना है कि हमलावरों ने बेहद करीब से गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उधर, अपने पीए की हत्या की खबर मिलते ही सुवेंदु अधिकारी मध्यमग्राम के लिए निकल चुके हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं।



कार की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें शीशे पर गोलीयों के निशान दिख रहे हैं। यह भी पता चला है कि बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी।

कौन थे चंद्रनाथ रथ?

चंद्रनाथ रथ सुवेंदु के करीबी थे। सुवेंदु की ओर से किसी से भी संवाद करना हो या बैठकों की देखरेख करना हो, इसकी जिम्मेदारी चंद्रनाथ ही संभालते थे। अभी खत्म हुए चुनाव के दौरान सुवेंदु के सभी व्यक्तिगत और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन इन्होंने ही किया। दो अधिकारी के साथ साथे की तरह रहते थे।

हमलावरों की तलाश शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके की नाकेबंदी करके हमलावरों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उधर, बीजेपी के कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इनमें कौस्तव बाग्यो, पीपुस कानडिया, शंकर घोष और शंकर चटर्जी शामिल हैं। पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है।

डिसमिस करना है तो करो, लेकिन नहीं दूंगी इस्तीफा

ममता की दो टूक



ममता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के अपने फैसले को जान-बूझकर किया गया एक विरोध प्रदर्शन बताया है। उन्होंने कहा कि वह इसके जरिए उस जनता का विरोध कर रही हैं जिसे भाजपा ने जबरदस्ती चुराया है। उन्होंने एक दिन पहले हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात का जिक्र किया था। तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बुआ की भावना को दोहराया। उन्होंने कथित तौर पर बांधली वाले बंगाल के जनता के खिलाफ एक वैध विरोध प्रदर्शन के तौर पर अपने पदों पर बने रहने को सही ठहराया। उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने पिछले पदों से इस्तीफा न दें।

ममता अपने फैसले पर अडिग

ममता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के अपने फैसले को जान-बूझकर किया गया एक विरोध प्रदर्शन बताया है। उन्होंने कहा कि वह इसके जरिए उस जनता का विरोध कर रही हैं जिसे भाजपा ने जबरदस्ती चुराया है। उन्होंने एक दिन पहले हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात का जिक्र किया था। तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बुआ की भावना को दोहराया। उन्होंने कथित तौर पर बांधली वाले बंगाल के जनता के खिलाफ एक वैध विरोध प्रदर्शन के तौर पर अपने पदों पर बने रहने को सही ठहराया। उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने पिछले पदों से इस्तीफा न दें।

सभी फैसले ममता बनर्जी पर निर्भर

पार्टी के प्रवक्ता और बेलियाघाट से विधायक कुणाल घोष ने कहा कि उनकी भविष्य की जिम्मेदारियों से संबंधित सभी फैसले ममता बनर्जी पर निर्भर करते हैं। घोष ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, किसे क्या जिम्मेदारी और काम दिया जाएगा, यह पूरी तरह से ममता दीदी के फैसले पर निर्भर करेगा। हम सभी उनके फैसले को मानने के लिए बाध्य होंगे। वह जो भी फैसला लेंगी, वह अंतिम होगा।

ममता की बैठक से 11 विधायक रहे नदारद

कोलकाता। बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बीच चुनाव नतीजों के दो दिन बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा बुधवार शाम बुलाई गई नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों की पहली बैठक में ही करीब 11 विधायक शामिल नहीं हुए। जिसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं।

चुनाव में तृणमूल की करारी हार के बीच ममता के कालीघाट स्थित आवास पर हुई इस अंदरूनी बैठक से जीत दर्ज करने वाले पार्टी के 80 में से करीब 11 विधायकों की अनुपस्थिति ने दल के भीतर संभावित असंतोष और अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को हवा दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, जिन नवनिर्वाचित सदस्यों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, उनमें मुर्शिदाबाद जिले के सागरादिवी से विधायक बायस विश्वास का नाम भी शामिल है। बायस विश्वास का बैठक में न पहुंचना खास तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हाल के दिनों में उनके रुख को लेकर पहले से ही अटकलें लाई जा रही थीं। बैठक से नदारद रहने वाले बाकी तृणमूल विधायकों के नामों का फिलहाल पता नहीं चला है।

संक्षिप्त खबरें

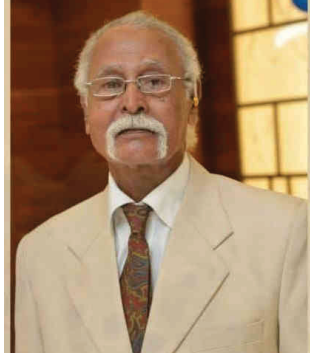
सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत, MCOCA मामले में नहीं मिली राहत

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (5 मई) को कथित उग्र सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को 200 करोड़ की जबरन वसूली के मामले में ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। हालांकि, लीना को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत दर्ज एक संबंधित मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रतीक जालान ने मंगलवार को लीना पॉलोस को दो मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने MCOCA के तहत मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है, वहीं दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसे मंजूरी दी। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लीना पॉलोस के पति चंद्रशेखर ने रेनबेक्स के पुराने प्रमोटर्स (शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह) की पत्नियों से 200 करोड़ उग्र थे। चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने खुद को लॉ फिनिस्ट्री का ऑफिसर बताया था और दोनों महिलाओं ने अपने पतियों की बेल दिलाने के लिए चंद्रशेखर को कई करोड़ रुपए दिए थे। चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस पर भी इस कथित जुर्म में शामिल होने का आरोप था।



बाणगंगा के संरक्षक व मुंबई मनपा के पूर्व नगर सेवक रांकी जोसेफ क्रास्टो का निधन

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता मुंबई। बाणगंगा क्षेत्र की पहचान और विरासत को संजोने वाले वरिष्ठ समाजसेवी और पूर्व नगरसेवक रांकी जोसेफ क्रास्टो का 27 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। उनके निधन से बाणगंगा समेत पूरे मुंबई के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। 5 सितंबर 1946 को जन्मे रांकी क्रास्टो ने अपने जीवन के पांच दशकों से अधिक समय बाणगंगा क्षेत्र की स्वच्छता, संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में समर्पित किया। स्थानीय लोगों के बीच उन्हें बाणगंगा का सच्चा प्रहरी और संरक्षक माना जाता था। 1970 और 1980 के दशक में जब यह ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा और गंदगी का शिकार हो रहा था, तब उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर सफाई और



संरक्षण अभियान का नेतृत्व किया, जिससे इस धरोहर को नई पहचान मिली। वे मुंबई महानगरपालिका में पांच बार नगरसेवक रहे और हमेशा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनका जीवन समाजसेवा, समर्पण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रेरक उदाहरण

रहा है। परिवार में वे अपने पुत्र क्लाइड क्रास्टो (एनसीपी-शरतचंद्र पवार पार्टी के सचिव व प्रवक्ता), पुत्री कैरोलिन क्रास्टो, बहू शांति क्रास्टो और पोते विवान क्रास्टो को छोड़ गए हैं। परिवार और करीबियों के अनुसार, वे हमेशा समाज और लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और कई मौकों पर लोगों की मदद के लिए आगे आए। उनके निधन पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि रांकी क्रास्टो का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। रांकी क्रास्टो के जाने से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा बाणगंगा क्षेत्र अपने एक सच्चे संरक्षक और हितैषी को खो बैठा है।

लोकभवन में RTI पर 'लीपापोती' का गंभीर आरोप अधूरी जानकारी और देरी से जवाब और प्रशासनिक पारदर्शिता पर लगा प्रश्नचिह्न

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता मुंबई। महाराष्ट्र के लोकभवन से जुड़ा एक RTI मामला अब गंभीर विवाद का रूप ले चुका है। राज्यपाल के प्रशासनिक अधिकारियों पर RTI के जवाब में 'लीपापोती' करने के आरोप लगे हैं, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। RTI आवेदक गिरीश केशवराव मिश्रा ने दावा किया है कि उन्हें मांगी गई जानकारी देने के बजाय भ्रामक, अधूरी और देरी से सूचना दी गई। आवेदक के अनुसार, उन्होंने 28 मार्च 2023 के सरकारी निर्णय (GR) को निरस्त करने वाली आधिकारिक अधिसूचना की प्रमाणित प्रति मांगी थी, लेकिन इसके स्थान पर लोकभवन सचिवालय ने एक आंतरिक "गाइडलाइन" पत्र भेज दिया। यह दस्तावेज ADC स्तर से जारी बताया गया है, जिससे यह संदेह और महारा हो गया है कि क्या बिना वैध अधिसूचना के ही नियमों में बदलाव कर दिया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब RTI के कई महत्वपूर्ण सवालों पर "Not Available" लिखकर जवाब दे दिया



दिन की सीमा के बाद का जवाब है, जिसे नियमों की अनदेखी माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी GR को निरस्त करने वाली वैध अधिसूचना मौजूद नहीं है, तो वह GR अब भी प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में लोकभवन प्रशासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर और भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आवेदक ने 5 मई 2026 को इस मामले में प्रथम अपील दायर कर दी है और साफ संकेत दिया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वह मामला महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग तक ले जाएंगे। इस बीच यह मुद्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों X पर भी तेजी से फैल रहा है, जहां राज्यपाल को टैग कर पारदर्शिता की मांग उठाई गई है। यह मामला अब केवल एक RTI विवाद नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता बनाम जवाबदेही की बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है। अब सबकी नजरें अपील प्रक्रिया पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि सच्चाई सामने आती है या नहीं।

आतंकी हमले की साजिश रचने वाले दो युवकों को एटीएस ने पकड़ा

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता लखनऊ। यूपी एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान गैंगस्टर्स और आईएसआई एजेंट के संपर्क में थे। आरोपी देश के संवेदनशील संस्थानों, पुलिस ठिकानों और सुरक्षाबलों पर हमले के साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में कुशीनगर निवासी कृष्णा मिश्रा (20) और बाराबंकी निवासी दानियाल अशरफ (23) शामिल हैं। एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आदिब जट और हम्मद के संपर्क में थे, जो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर सेव मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए इनकी वीडियो कॉलिंग और वॉट्स नोट्स के साक्ष्य भी मिले हैं। क्वार्टर एफ युप कॉल के जरिए संदिग्ध विदेशी नंबरों से बातचीत कर देशविरोधी साजिशें रची जा रही थीं।

बंगाल में नई सरकार की तैयारियां शुरू 9 मई को BJP का शपथ समारोह

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शपथ समारोह में प्रधानमंत्री, एनडीए व भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। दो दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग के बाद 4 मई को मतों की गणना हुई। जिसमें सत्ता धारी दल तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया है।

बंगाल के लिए सड़क पर क्यों नाचा ब्रिटिश नेता

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक ब्रिटिश नेता ब्रिटेन की सड़कों पर खड़े होकर नाचने लगे। इस तस्वीर ने ब्रिटेन में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जश्न मनाता देख पाकिस्तान और बांग्लादेश छाती पीट कर रो रहे हैं। विदेशी मीडिया भी यह नहीं पचा पा रही कि बीजेपी बंगाल में कैसे जीत सकती है। कैसे पीएम मोदी और ताकतवर हो सकते हैं।



बंगाल तो बांग्लादेश बनने से बाल-बाल बच गया, लेकिन इंग्लैंड में लगे इस पोस्टर ने बता दिया है कि ब्रिटेन को अब इस्लामिक देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल एक ब्रिटिश नेता बाँब ब्लैकमैन ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के साथ बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते दिखे। पश्चिम बंगाल के नतीजे आते ही बाँब ब्लैकमैन ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के साथ नाचने लगे। ब्रिटिश सांसद बाँब ब्लैकमैन ने खुशी जताई कि बंगाल में बीजेपी आ गई है। आपको बता दें कि बाँब ब्लैकमैन लगातार ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के अधिकारों की बात करते आए हैं। बाँब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में

मारे जा रहे हिंदुओं की भी आवाज उठाई थी। लेकिन जिस वक्त बाँब ब्लैकमैन हिंदुओं के साथ नाच रहे थे, ठीक उसी वक्त इंग्लैंड की सड़कों पर कुछ पोस्टर लगे दिखे। बंगाल के चुनावों में तो सनातन की जीत हो गई। लेकिन इंग्लैंड देखिए किस तरह जा रहा है। 7 मई को लंदन में 5000 से ज्यादा काउंसिल सीटों पर वोटिंग होनी है। यह लंदन में लोकल बाँडी के इलेक्शन हैं। ब्रिटेन में कट्टर इस्लाम और पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे टॉमी रॉबिंसन ने एक तस्वीर डालते हुए लिखा कि मांडन इंग्लैंड में ऐसे चुनाव हो रहे हैं। दरअसल टॉमी रॉबिंसन दिखा रहे हैं कि लोकल बाँडी के चुनावों में पाकिस्तान और दूसरे देशों से आए मुस्लिम कैंडिडेट हावी हो चुके हैं। चुनाव लंदन में है लेकिन लड़ने वाले ज्यादातर शायद पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। कई इलाकों में तो आमने-सामने मुस्लिम कैंडिडेट्स ही हैं। यानी कोई भी जीते लेकिन उस इलाके को मिलेगा मुस्लिम कैंडिडेट ही। अंग्रेजों का तो नामनिर्वाचन तक नहीं है। टॉमी रॉबिंसन से लेकर डॉनल्ड ट्रंप तक बोल चुके हैं कि इस्लाम ब्रिटेन पर हावी हो चुका है। ब्रिटेन में कहीं भी चुनाव हो वहां अब मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े होते हैं। ब्रिटेन के कई शहरों में अब मुस्लिम मेयर बन चुके हैं। अब तो ब्रिटेन में शरिया अदालत तक शुरू हो चुकी है।

मध्य रेलवे की बड़ी कार्रवाई: विदेशी पर्यटक कोटे के दुरुपयोग के 39 मामले उजागर

3.56 लाख रुपये जुर्माना वसूला

आर.एस. नेटवर्क। संवाददाता मुंबई। मध्य रेलवे ने विदेशी पर्यटक (एफटी) कोटे के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए 39 मामलों का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में कुल 3,56,916 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। यह मामला 4 फरवरी 2026 को ट्रेन संख्या 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस में सामने आया, जहां कुछ भारतीय यात्री विदेशी पर्यटक कोटे के टिकट पर बिना आवश्यक दस्तावेजों के यात्रा करते पाए गए। **जांच में सामने आई बड़ी अनियमितताएं** मध्य रेलवे द्वारा भविष्य की तारीखों के बुकिंग डेटा का विश्लेषण किया गया। जांच में पाया गया कि 24 अप्रैल से 11 जून 2026 के बीच 31 ट्रेनों के लिए कुल 174 पीएनआर विदेशी पर्यटक कोटे के तहत बुक किए गए थे। विशेष जांच अभियान के दौरान 39 पीएनआर संदिग्ध पाए गए, जिनमें 121 यात्री नियमों का उल्लंघन करते हुए यात्रा कर रहे थे। इन यात्रियों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया।

सौदें रह कर अन्य यात्रियों को दी गई नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को उनकी बर्थ पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में वे सीटें आरएसी और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को आवंटित कर दी गई। **एजेंटों की भूमिका की जांच** इस मामले में किसी अधिकृत बुकिंग एजेंट की संलिप्तता की जांच के लिए आईआरसीटीसी से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान के लिए जांच जारी है। **रेलवे की अपील** रेलवे ने स्पष्ट किया है कि गलत कोटे के तहत टिकट बुक करना रेलवे कानून के तहत दंडनीय अपराध है। यात्रियों को यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे कर्मचारियों, हेल्पलाइन नंबर 139 या 'रेल मदद' ऐप के माध्यम से दें। साथ ही यात्रा से पहले अपने टिकट की वैधता और सही जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

भिवंडी में किसान सभा का प्रांत कार्यालय पर जोरदार मोर्चा

आर.एस. नेटवर्क। संवाददाता भिवंडी। विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने बुधवार को भिवंडी प्रांत कार्यालय पर जोरदार मोर्चा निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में आयोजित इस मोर्चे में ठाणे-पालघर जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ शाहपुर और भिवंडी क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। किसानों ने सरकार से पहले से स्वीकृत मांगों को लेकर प्रांत कार्यालय तक मोर्चा निकाला, जहां पहुंचने के बाद किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वन पट्टों पर काबिज जमीन को खेती करने वाले पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दर्ज करने, बढ़ते बिजली बिलों के लिए जिम्मेदार स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने की मांग/साथ ही किसानों ने सभी जरूरतमंद परिवारों को घरकुल योजना का लाभ देने, जल जीवन मिशन के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने



और प्रत्येक परिवार को 35 किलो राशन अनाज उपलब्ध कराने की भी मांग की। साथ ही राशन वितरण में कथित भ्रष्टाचार की जांच और श्रमिक विरोधी चार श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बकरीद पर बली दिए गए जानवरों के अवयवों को नहीं उठायेगे मजदूर सफाईकर्मों

आर.एस. नेटवर्क। ठाणे संवाददाता भिवंडी। भिवंडी मजदूरों के सफाई कर्मचारी इस वर्ष बकरीद पर दिए जाने वाले जानवरों की कुर्बानियों के बाद निकलने वाले बेस्टेज को नहीं उठाएंगे। उक्त घोषणा मजदूर यूनियनों ने महापौर व उपमहापौर के साथ हुए बैठक के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर यूनियनों ने कहा है कि जो लोग जानवरों की बली देंगे, वही अब जानवरों के बेस्टेज को भी हटाए। इतना ही नहीं यूनियनों का कहना है हर दिन की तरह साफ सफाई का अन्य कार्य सफाई कर्मचारी ही करेंगे। मजदूर यूनियनों के इस निर्णय से मजदूर प्रशासन के हाथ पाव फूल गए हैं।



हवाला देकर उक्त कार्य सफाई कर्मचारियों से करावती आ रही है। सफाई न करने पर कार्रवाई का धौंस देकर डराती है लेकिन इस वर्ष भी मजदूर सफाई कर्मचारी जानवरों की बली के बाद निकलने वाले बेस्टेज को नहीं हटाएंगे। यूनियनों का कहना है कि जो लोग जानवरों की बलि देंगे वही लोग उनके अवशेष को गोनी में भरकर कचरा गाड़ी में डालें, जिसके बाद मजदूर सफाई कर्मियों उसे उठाकर ले जायेंगे। साथ ही कुर्बानि सेंटर की

पानी डालकर सफाई करने के साथ दवा का छिड़काव को करेंगे। यूनियनों ने हाईकोर्ट का हस्ताक्षर देते हुए बताया है कि बकरीद को लेकर दायर जनहित याचिका के बाद 5 जुलाई 2022 को न्यायधीश एस के मेमन व एम एस कार्णिक ने कुर्बानि संबंधित निर्देश में बली देने वाले को बेस्टेज भी खुद हटाने का निर्देश दिया था। इन्हें महापौर नारायण चौधरी ने यूनियनों की बात सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि यूनियनों द्वारा सफाई कर्मचारियों के हित में किए जा

रहे मांग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बकरीद से पहले मजदूर आयुक्त के साथ बैठक कर इसको अमल में लाया जाएगा। इस दौरान भिवंडी म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र कबाड़ी, लेबर फ्रंट के अध्यक्ष संतोष चौहान, विकास निकम, चंद्रकांत सोनवाने, दीपक राव, भारत तंवी, रविचंद्र गायकवाड़ व श्याम गायकवाड़, सुनील बांगर सहित सभी यूनियनों अध्यक्ष व सचिव इस बैठक में मौजूद थे।

भिवंडी में अवैध मोबाइल टावरों के सामने लाचार मजदूर प्रशासन, वसूली फिसड़ी

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता भिवंडी। भिवंडी मजदूर अंतर्गत लगे अवैध मोबाइल टावरों से टैक्स वसूली को लेकर प्रशासन लाचार साबित हो रहा है। शहर में विभिन्न कंपनियों के लगे 284 मोबाइल टावरों पर मजदूर प्रशासन का तक्राबन 40 करोड़ रुपया टैक्स बकाया है। जिससे प्रशासन न बकाया टैक्स की वसूली कर पा रही है न ही उन पर कार्रवाई कर पा रही है। क्योंकि मजदूर नोटिस के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जबकि मजदूर आर्थिक कंगाली से जूझ रही है।

भिवंडी मजदूर कर्मसूचक अधिकारी गिरीश घोषटेकर ने बताया कि मजदूर अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध मोबाइल कंपनियों के कुल 284 मोबाइल टॉवर्स शहर की गगनचुंबी इमारतों पर लगे हैं। जिसमें बीएसएनएल के 17, एटीसी के 57, जिटीएल के चार, इंडस के 63, रिलायंस कंपनी के 27, जिओ

के 102, यूनिटी के 2, एयरटेल के 1, वोडाफोन के 1, मोबाइल कंपनियों के टॉवर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल टॉवरों में से रिलायंस जिओ के 70 मोबाइल टॉवर को छोड़कर बाकी सभी 214 टॉवर अवैध तरीके से बिना मजदूर प्रशासन से किसी प्रकार परमिशन लेकर लगाए गए हैं। मजदूर अधिकारी का आरोप है कि उक्त मोबाइल कंपनियों द्वारा बिना मजदूर प्रशासन से कोई एनओसी लिए इमारत मालिकों को लालच देकर मजदूर द्वारा घोषित धोकादायक इमारतों पर भी मोबाइल टावर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इमारतों पर मोबाइल टावर लगाने वाली नामचीन कंपनियों इमारत मालिकों व सोसाइटी को प्रतिमाह भाड़ा स्वरूप करीब 15 से 25 हजार रुपया अदा करती हैं। इन मोबाइल टावरों पर मजदूर का कुल 39 करोड़, 52 लाख 92 हजार 302 करोड़ रुपया बतौर टैक्स राजस्व बकाया है। जिस में से नियमित टैक्स

जनगणना और बीएलओ कार्यों से परेशान शिक्षकों को 'शिक्षण क्रांति संगठन' की मांग से मिलेगी राहत

आर.एस. नेटवर्क। संवाददाता भिवंडी। मतदाता सूची पुनरीक्षण और जनगणना कार्यों के कारण शिक्षा पर अतिरिक्त काम का बोझ पड़ने से शिक्षक काफी परेशान हैं। उन्हें राहत दिलाने के लिए 'शिक्षण क्रांति संगठन' द्वारा दिए गए ज्ञापन के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनगणना और बीएलओ इयूटी पर तैनात कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में शिक्षण क्रांति संगठन के राज्य अध्यक्ष सुधीर देवराव घामस, राज्य संगठक आर.डी. पाटिल, महानगर जिला अध्यक्ष गजानन पाटिल जिला सचिव थॉमस शिंगारे और प्रशासन की ओर से प्रशासनिक अधिकारी भारत बोरनारे, विकास नंदनवर, विलास लिखारे सहित प्रभावित कर्मचारी उपस्थित थे। शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भारत बोरनारे ने कहा कि कुछ मांगों को



स्वीकार कर लिया गया है और शेष मांगों को नगर निगम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर राहत देने का निर्णय लिया जाएगा। संगठन की मांग के अनुसार, मुख्यध्यापकों को जनगणना और बीएलओ कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। गंधीर बीमारियों से ग्रस्त और सेवानिवृत्ति में 6 महीने से कम समय शेष रहने वाले कर्मचारियों को इस काम से छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को बीएलओ या जनगणना में से केवल एक ही काम दिया जाएगा। इस कार्य के लिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए स्व-सहायता स्कूलों के कर्मचारियों से भी यह कार्य करने का आह्वान किया गया है। अधिकारियों ने

स्पष्ट किया कि सभी विभागों के कर्मचारियों को समान अनुपात में लिया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी गई या केस दर्ज करने की धमकी दी गई, तो धमकी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कराया जाएगा और काम का बहिष्कार किया जाएगा। संगठन ने मांग की है कि इन कार्यों में लगे सभी कर्मचारियों का 1 करोड़ रुपये का बीमा कराने के लिए जिलाधिकारी और सरकार से संपर्क किया जाए। साथ ही, इस कार्य के बदले मिलने वाला मानदेय सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिए।

पालघर अत्याचार मामला: पीड़िता को न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष, आरोपी को न मिले जमानत: डॉ. नीलम गोरे

आर.एस. नेटवर्क। संवाददाता पालघर। पालघर जिले के कासा पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ कथित "भौंदू बाबा" द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले ने गंधीर रूप ले लिया है। इस घटना पर महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरे ने सख्त रुख अपनाते हुए पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की तथा न्याय दिलाने का भरोसा दिया। डॉ. गोरे ने स्पष्ट कहा कि पीड़ित परिवार की एकमात्र मांग न्याय है और किसी भी स्थिति में आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर मामले की त्वरित जांच और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की बात कही। **पीड़िता के भविष्य पर विशेष ध्यान** डॉ. गोरे ने बताया कि पीड़िता आगे पढ़ाई कर पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की सभी योजनाओं के माध्यम से उसकी शिक्षा और करियर को पूरा समर्थन दिया जाएगा। दबाव बनाने वालों पर भी होगी कार्रवाई



उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी की मदद करता है, गवाहों को प्रभावित करता है या किसी भी प्रकार का दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। **डीएनए जांच और गवाह सुरक्षा पर जोर** मामले को मजबूत बनाने के लिए डीएनए जांच सहित सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाएंगे। साथ ही गवाह संरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने जताया भरोसा इस दौरान डॉ. गोरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात कर पूरी जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने पीड़िता और उसके परिवार से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएगा। उन्होंने पीड़िता की शिक्षा की जिम्मेदारी भी लेने की बात कही। **'मनोधैर्य' योजना के तहत मदद** प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता

को 'मनोधैर्य' योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता, पुलिस सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और मानसिक परामर्श तुरंत उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। **अंधविश्वास के खिलाफ सख्त** डॉ. गोरे ने अंधविश्वास और भौदुंगीरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। **फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग** राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अपेक्षित अदालतों की तुलना में कम अदालतें कार्यरत हैं, जिससे मामलों में देरी हो रही है।

ठाणे सिविल अस्पताल में PCOD क्लिनिक का उद्घाटन

आर.एस. नेटवर्क। संवाददाता ठाणे। राज्य में महिलाओं का स्वास्थ्य बनाए रखने और हार्मोनल प्रॉब्लम PCOD जो खासकर शहरी इलाकों में अविवाहित युवतियों और प्रिओडक्टिव उम्र की महिलाओं में बढ़ रही है, का समय पर इलाज देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज पूरा राज्य में PCOD क्लिनिक शुरू किए गए हैं। इसी कैंपेन के तहत 6 मई को सिविल सर्जन डॉ. कैलाश पवार के गाइडेंस में PCOD क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त सिविल सर्जन डॉ. धीरज महंगड़े ने PCOD के बारे में जरूरी गाइडेंस दी। उनके साथ, एक्सपर्ट एकोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल की लेडी एम्पलॉई ने मौजूद महिलाओं और मरीजों को PCOD के बारे में डिटेल्स में गाइडेंस दी। क्लिनिक का प्रारूप एवं उपलब्ध सेवाएं यह पीसीओडी क्लिनिक अब जिला अस्पताल में हर बुधवार को 'मेनोपॉज ओपीडी' के साथ

नियमित रूप से खुला रहेगा। इस क्लिनिक में महिलाओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जांच। हार्मोनल परिवर्तन के आधार पर आवश्यक चिकित्सा परीक्षण। एकीकृत दृष्टिकोण दवा। स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श। विशेषज्ञों द्वारा आहार एवं जीवनशैली पर विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बदलती जीवनशैली और मानसिक तनाव के कारण युवतियों में पीसीओडी बढ़ रहा है। अगर सही समय पर निदान और इलाज किया जाए तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। उद्घाटन के बाद क्लिनिक में आए मरीजों की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवा एवं परामर्श दिया गया। प्रशासन ने अधिक से अधिक महिलाओं से जिला अस्पताल ठाणे में इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

ठाणे में 'स्व-गणना' की शुरुआत: मेयर-डिरी मेयर ने किया सेल्फ एन्यूमरेशन, नागरिकों से QR कोड के जरिए भागीदारी की अपील

आर.एस. नेटवर्क। संवाददाता ठाणे। जनगणना 2027 की प्रक्रिया को गति देते हुए ठाणे महानगरपालिका में पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मजदूरों के स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल हॉल में किया। इसी क्रम में मेयर शर्मिला पिंपलोलकर और डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल ने खुद 'स्व-गणना' (सेल्फ एन्यूमरेशन) कर नागरिकों को नई व्यवस्था का संदेश दिया। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे QR कोड के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और प्रशासन का सहयोग करें। **जागरूकता के लिए विशेष पहल** जनगणना को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष मैसकांट और प्रतीकात्मक कटआउट तैयार किए हैं, जिन्हें 'विकास' और 'प्रगति' नाम



दिया गया है, ताकि आम नागरिकों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। **सही जानकारी देना जरूरी** मजदूर आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना के लिए घर आने वाले गणनाकारों (एन्यूमेरेटर) को सही और पूरी जानकारी दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के विकास और

कल्याण के लिए सटीक आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। **15 मई तक चलेगा पहला चरण** सहायक आयुक्त सचिन बोरसे ने जानकारी दी कि जनगणना 2027 का पहला चरण 15 मई 2026 तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए मजदूर मुख्यालय में हेल्थ डेस्क स्थापित किया गया है। **शहर में लगाए गए QR कोड** शहर के विभिन्न स्थानों पर QR कोड लगाए गए हैं। नागरिक इन कोड को स्कैन कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। स्व-गणना पूरी होने के बाद उन्हें एक यूनिक नंबर प्राप्त होगा, जिसे घर पर आने वाले एन्यूमेरेटर को दिखाना आवश्यक होगा। **प्रशासन ने नागरिकों से अपील** की है कि वे इस डिजिटल पहल का अधिक से अधिक उपयोग कर जनगणना को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

ठाणे में मोबाइल चोरी की तीन घटनाएं, भीड़ और झांसा बन रहा अपराधियों का हथियार

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता ठाणे। शहर के विभिन्न इलाकों में मोबाइल फोन चोरी की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। मुंबा रेलवे स्टेशन, माजिवाड़ा और नौपाड़ा इलाके में हुई इन घटनाओं के बाद पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। **मुंबा स्टेशन पर भीड़ में चोरी** मुंबा रेलवे स्टेशन पर भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर ने 60 वर्षीय अब्दुल कुदूस खान का महंगा मोबाइल फोन चुरा लिया। शिकायत के अनुसार, वे 2 मई को एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद स्टेशन पहुंचे थे। रात करीब 10:49 बजे सीपीएसपी जाने वाली स्लो लोकल के जनरल डिब्बे में चढ़ते समय उनकी पतलून की जेब में रखा मोबाइल फोन गायब हो गया। चोरी हुए मोबाइल की कीमत 30,999 रुपये बताई गई है। इस मामले में ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। **माजिवाड़ा में झांसा देकर मोबाइल चोरी** दूसरी घटना माजिवाड़ा इलाके में सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने बातचीत का बहाना कर घर से मोबाइल फोन चुरा लिया। शिकायतकर्ता सुनील लक्ष्मण राठौड़ (25) ने कर्पूबावड़ी पुलिस स्टेशन

में मामला दर्ज कराया है। 4 मई की सुबह जब वे नाइट शिफ्ट के बाद घर पर सो रहे थे, उसी दौरान चोरी की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। मुंबा रेलवे स्टेशन, माजिवाड़ा और नौपाड़ा इलाके में हुई इन घटनाओं के बाद पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। **मुंबा स्टेशन पर भीड़ में चोरी** मुंबा रेलवे स्टेशन पर भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर ने 60 वर्षीय अब्दुल कुदूस खान का महंगा मोबाइल फोन चुरा लिया। शिकायत के अनुसार, वे 2 मई को एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद स्टेशन पहुंचे थे। रात करीब 10:49 बजे सीपीएसपी जाने वाली स्लो लोकल के जनरल डिब्बे में चढ़ते समय उनकी पतलून की जेब में रखा मोबाइल फोन गायब हो गया। चोरी हुए मोबाइल की कीमत 30,999 रुपये बताई गई है। इस मामले में ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। **माजिवाड़ा में झांसा देकर मोबाइल चोरी** दूसरी घटना माजिवाड़ा इलाके में सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने बातचीत का बहाना कर घर से मोबाइल फोन चुरा लिया। शिकायतकर्ता सुनील लक्ष्मण राठौड़ (25) ने कर्पूबावड़ी पुलिस स्टेशन



हिंदी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान

पत्र व्यवहार: रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महरा, पत्रा वाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113

ईमेल: rastriyaswabhimaaan@gmail.com

04

मुंबई, गुरुवार, 6 मई 2026

महाराष्ट्र

epaper.rashtriyaswabhimaaan.com
www.rashtriyaswabhimaaan.com

विकास के साथ चेंदनी कोलीवाड़ा की पहचान बचाने की मांग

सीमांकन प्रक्रिया में स्थानीयों की भागीदारी पर जोर

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
ठाणे। महाराष्ट्र सरकार के 29 जनवरी 2026 के निर्णय के तहत कोकण क्षेत्र में कोलीवाड़ों के सीमांकन (डिमांकेशन) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ठाणे के चेंदनी कोलीवाड़ा का भी सीमांकन प्रस्तावित है। इस पर चेंदनी कोलीवाड़ा कोली जमात ट्रस्ट ने प्रशासन से मांग की है कि स्थानीय कोली समुदाय को विश्वास में लिए बिना यह प्रक्रिया लागू न की जाए।



ट्रस्ट ने अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल को सौंपे गए आवेदन में सवाल उठाया है कि क्या विकास के नाम पर कोलीवाड़ा के अस्तित्व और पहचान से समझौता किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमांकन केवल जमीन का नहीं, बल्कि पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत का भी होना चाहिए।

विकास परियोजनाओं से बड़ी चिंता मनपा क्षेत्र में चल रही अर्बन रिन्यूअल (क्लस्टर) योजना, अंडरग्राउंड मेट्रो,

रेलवे लाइन समानांतर सड़क, कोस्टल रोड और पटनी-कोपरी ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है। आशंका है कि इन परियोजनाओं से चेंदनी कोलीवाड़ा की मूल बस्ती प्रभावित हो सकती है।

इससे पहले ट्रांस हार्बर रेलवे परियोजना के चलते कई घर प्रभावित हो चुके हैं। लगातार हो रहे शहरीकरण के कारण कोली समुदाय के पारंपरिक मछली पकड़ने के व्यवसाय और जीवनशैली पर भी खतरा मंडरा रहा है।

पारंपरिक ढांचे को शामिल करने की मांग

ट्रस्ट ने प्रस्तावित सीमांकन में गांव के विस्तारित हिस्सों के साथ-साथ मछली पकड़ने के क्षेत्र, मैंग्रोव, नाव और जाल रखने की जगह, पारंपरिक रास्ते, आंतरिक सड़कें, सार्वजनिक खुली जगहें, तथा गांव के देवता और मंदिर परिसर को शामिल करने की मांग की है।

संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र

चेंदनी कोलीवाड़ा को ठाणे की मूल संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। यहां सक्रिय सहकारी मछली पकड़ने वाली संस्थाएं न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि परंपराओं को भी जीवित रखती हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष अमरीश थानेकर, डिमांकेशन समिति के सदस्य सचिन थानेकर और आनंद कोली ने आवेदन देते समय प्रशासन से अपील की कि विकास योजना बनाते समय कोलीवाड़ा और कोली समुदाय के अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाए।

बदलापुर में 13 से 17 मई तक होगा 'छत्रपति शिवाजी महाराज कप' राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
ठाणे। ठाणे जिले के बदलापुर में 13 से 17 मई तक 'छत्रपति शिवाजी महाराज कप' राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुंबई स्थित सहाय्यी गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।



बैठक के दौरान प्रतियोगिता के आधिकारिक बोधचिह्न (लोगो) का अनावरण भी किया गया। यह प्रतियोगिता 18 और 21 वर्ष आयु वर्ग के लड़के एवं लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन खेल विभाग और कुलांगव-बदलापुर नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में होगा।

खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं

ट्रस्ट के अध्यक्ष अमरीश थानेकर, भोजन, खेल मैदान की तैयारी और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय आवास और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

आयोजन के लिए आवश्यक 25 लाख रुपये की राशि CIDCO के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया।

खेल परिसर कार्यों की समीक्षा

इसके अलावा ठाणे मंडल खेल परिसर में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई, ताकि भविष्य में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

ये रहे प्रमुख उपस्थित

इस बैठक में विधायक किसान कथोरे, कुलांगव-बदलापुर नगर परिषद की अध्यक्ष रचिता घोरपड़े, उपमुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, खेल विभाग के उपनिदेशक नवनाथ फरताडे, जिला खेल अधिकारी सुवर्णा बरताके, जिला सिविल सर्जन डॉ. कैलाश पवार सहित महाराष्ट्र वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ठाणे के जिला कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन ने विश्वास जताया है कि यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों को मंच देगी, बल्कि ठाणे जिले में खेल संस्कृति को भी नई पहचान देगी।

दौंड में 9 वर्षीय बच्ची की हत्या से फैली सनसनी, डॉ. नीलम गोरे ने लिया संज्ञान

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
पुणे (विशेष प- पुणे जिले के दौंड तालुका स्थित देऊलगांव राजे गांव में 9 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस हृदयविदारक घटना पर महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरे ने गंभीर संज्ञान लेते हुए पुणे प्रामीण पुलिस अधीक्षक को लिखित निवेदन सौंपा है। अपने निवेदन में डॉ. गोरे ने मामले की गहन जांच कराने, सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाने तथा इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को सक्षम वकील उपलब्ध कराने के साथ-साथ गवाहों, विशेष रूप से घटना के प्रत्यक्षदर्शी छोटे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।

"घटना ने मन को झकझोर दिया"
डॉ. गोरे ने कहा, "यह बेहद दुखद और मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक मासूम बच्ची की मामूली कारणों से हत्या होना समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।

ऐसे मामलों में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए।"

गवाह बच्चे की सुरक्षा और काउंसलिंग जरूरी
उन्होंने कहा कि घटना के गवाह छोटे बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रखा जाए और उसका मानसिक समुपदेशन कराया जाए, ताकि वह इस सदमे से उबर सके। डॉ. गोरे ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में सांगली जिले के आटपाड़ी में भी दो बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई थी, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार और समाज स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सख्त कार्रवाई की मांग

डॉ. गोरे ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

ठाणे में चोरी और आग की घटनाएं: मेले में पर्स चोरी, खड़ी कार गायब, घर में लगी आग

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता

ठाणे। शहर में अलग-अलग स्थानों पर चोरी और आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे नागरिकों में चिंता का माहौल है। पुलिस ने मामलों में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मेले में महिला की पर्स चोरी
बलुकुम नाका क्षेत्र में साई बाबा जयंती के अवसर पर लगे मेले में भीड़ का फायदा उठाकर एक चोर ने 31 वर्षीय पूजा अनिल यादव का पर्स चोरी कर लिया। इस संबंध में कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, 2 मई को मेले में मौजूद पूजा यादव ने अपना मंगलसूत्र टूटने के कारण उसे पर्स में रख लिया था। इसी दौरान जब वह अपने पति से मोबाइल पर बात कर रही थी, अज्ञात चोर ने उनके पर्स से 14 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र, 8,000 रुपये नकद और

आधार कार्ड, बैंक कार्ड व वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 58,000 रुपये बताई गई है।

खड़ी कार चोरी

ठाणे के लोकमान्यनगर पाडा नंबर 4 इलाके में खड़ी एक कार चोरी होने की घटना सामने आई है। इस मामले में वर्तकनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता संदीप शेटके (33) ने 2 मई की दोपहर काम खत्म करने के बाद अपनी कार ज्ञानोदय स्कूल के सामने सड़क पर खड़ी की थी। 4 मई की सुबह जब वे वहां पहुंचे तो कार गायब थी। आसपास और रिसर्चदारां से पूछताछ के बाद भी कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। चोरी हुई कार की कीमत लगभग 1 लाख रुपये बताई गई है।

ओवाला में घर के बेडरूम में लगी आग

घोड़बंदर रोड स्थित ओवाला नाका इलाके में सोमवार रात एक घर के बेडरूम में आग लग गई। यह घटना रात करीब 11:45 बजे की है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, विवाट टीम, महावितरण के कर्मचारी और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद रात 12:50 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस आग में एसी, बिस्तर, अलमारी, टीवी और बिजली के तार जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।



पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विजय के अवसर पर वर्ली के विरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष बालगोविंद तिवारी को मिठाई खिलाकर शुभकामना देते हुए प्रसन्न मुन्ना में भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी।



KEM हॉस्पिटल के नूतन डीन डॉक्टर हरीश पाठकजी का स्वागत करते भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य परिषद सदस्य विजय गोवळकर



नई 'फोर्स ट्रैवेलर एन' रेंज लॉन्च, अब और ज्यादा आधुनिक और आरामदायक

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता

मुंबई। फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने अपनी नई फोर्स ट्रैवेलर एन रेंज लॉन्च की है, जिसे एंजुलेस, स्कूल बस और डिलीवरी वैन जैसे उपयोगों के लिए तैयार किया गया है।

नई रेंज में कार जैसा ड्राइवर केबिन, डिजिटल डिस्प्ले और 9-इंच टचस्क्रीन जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही बेहतर सीटिंग, कम शोर

और कंपन, तथा नया एयर कंडीशनिंग सिस्टम सफर को अधिक आरामदायक बनाता है। कंपनी के एमडी प्रसन्न फिरोदिया के अनुसार, इस मॉडल को ग्राहकों, ड्राइवरों और फ्लीट ऑपरेटोर्स के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस और कम मटेनेंस लागत सुनिश्चित हो सके। कंपनी अब धीरे-धीरे पुराने ट्रैवेलर मॉडलस की जगह इसी नई 'एन' रेंज को लाने की योजना बना रही है।

छह पहिएदार कंटेनर और शराब के 1,450 बक्से जब किए गए, 2 गिरफ्तार

दावाइयों के बिल बनाकर गोवा में निर्मित शराब की तस्करी का पर्दाफाश हुआ

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
ठाणे। गुप्त सूचना मिली थी कि दवा के नाम पर फर्जी चालान बनाकर छह पहियों वाले कंटेनर में गोवा में बनी शराब का जखीरा ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर राज्य उत्पाद शुल्क फ्लॉइंग स्क्वाड ने 5 मई, 2026 को शाम लगभग 6:15 बजे आर.सी. पाटिल टोल नाका और माजिवाड़ा के बीच संदेह होने पर कंटेनर को रोका और शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। राज्य उत्पाद शुल्क स्क्वाड ने छह पहियों वाले कंटेनर के साथ शराब के 1,450 बक्से जब किए और परिवहन में शामिल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।



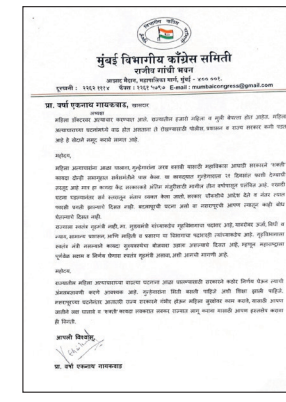
उत्पाद शुल्क अधीक्षक प्रवीण तांबे साहब, उप अधीक्षक आनंद पवार, ठाणे-1 और उप अधीक्षक रत्नमाला गायकवाड़ ने सूचना दी कि गोवा में निर्मित शराब को किसी विदेशी राज्य से लाया जा रहा है। इसके बाद टीम आर.सी. पाटिल टोल नाका और माजिवाड़ा रोड, ठाणे के बीच गश्त कर रही थी। जब टीम ने कंटेनर को रोककर उसकी

जांच की, तो उसमें 180 मिलीलीटर की सीलबंद रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की (गोवा में निर्मित) की बोतलें मिलीं। टीम ने मंगलवार को कार्रवाई में शराब के 1,450 बक्से जब किए। टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ 65 लाख 11 हजार 500 रुपये मूल्य के छह पहिएदार कंटेनरों के साथ शराब का भंडार जब्त किया।

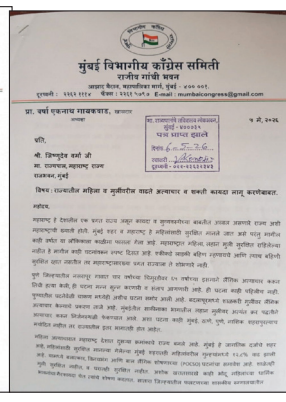
महिला सुरक्षा पर राज्यपाल हस्तक्षेप करें, 'शक्ति' कानून लागू हो और पूर्णकालिक गृहमंत्री नियुक्त किया जाए : वर्षा गायकवाड़

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में बढ़ते महिला अत्याचार के मामलों को लेकर वर्षा गायकवाड़ ने राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल से कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने और 'शक्ति' कानून को जल्द लागू कराने की अपील की है।
महिला सुरक्षा पर जताई चिंता
अपने पत्र में गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र को पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ती घटनाओं ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि नसरपुर, बदलापुर, चाकण और मुंबई के साकीनाका जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि महिलाएं और बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।



'शक्ति' कानून लागू करने की मांग
गायकवाड़ ने बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान 'शक्ति' कानून दोनों सदनों में पारित किया गया था, जिसमें गंभीर अपराधों के मामलों में 21 दिनों के भीतर सख्त



सजा का प्रावधान है। हालांकि, यह कानून पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है। उन्होंने इसे जल्द लागू करने की मांग की।
पूर्णकालिक गृहमंत्री की जरूरत
उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा

कि वर्तमान में गृह विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, जिससे इस विभाग पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में एक पूर्णकालिक और सक्षम गृहमंत्री की नियुक्ति आवश्यक है।
अपराधों में बढ़ोतरी पर चिंता
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में महिला अपराधों में वृद्धि हुई है और मुंबई जैसे शहर में भी ऐसे मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गायकवाड़ ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है ताकि अपराधियों में कानून का डर पैदा हो सके। अंत में उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे इस गंभीर विषय पर तुरंत ध्यान देते हुए महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दें।